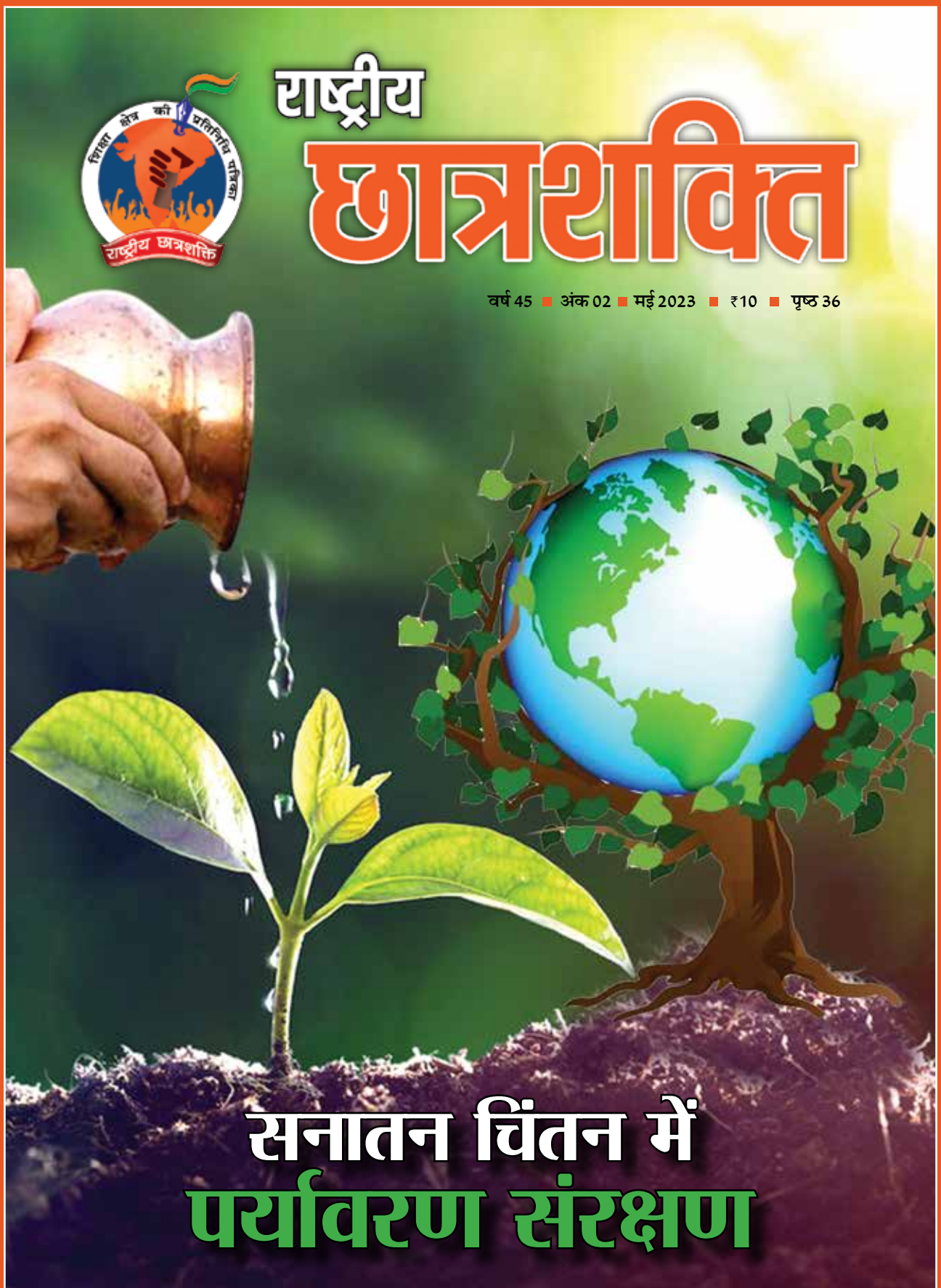

राष्ट्रीय

छात्रशक्ति

वर्ष 45 ■ अंक 02 ■ मई 2023 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 36

सनातन चिंतन में पर्यावरण संरक्षण

देहरादून : दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक का शुभारंभ करते अभाविप राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल एवं संगठन मंत्री आशीष चौहान

बेगुसराय : अग्निकांड पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण करते हुए अभाविप कार्यकर्ता

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 45, अंक 02
मई 2023

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

अबकी बार

05

सनातन चिंतन में पर्यावरण संरक्षण

विश्व इतिहास में पहली बार रशल कार्सन नामक अमरीकी महिला वैज्ञानिक ने वर्ष 1962 में छपी अपनी पुस्तक 'साइलेंट स्प्रिंग' में मानवजनित क्रिया-कलापों (जैसे रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों...

संपादकीय	04
सभी को सहभागी बनना होगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए	08
दिल्ली में एग्रीविजन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, कृषि उद्यमिता पर हुआ सारगर्भित संवाद	10
SCO FOREIGN MINISTERS MET IN DELHI UNDER A LOOMING CLOUD	12
छात्र–छात्राओं की अनेकों समस्याओं का समाधान करेगा 'नेशनल मेंटरिंग मिशन'	15
जनसख्या में वृद्धि : बोझ या वरदान...!!!	16
SAVISHKAR INDIA EXPLORING STARTUP ECOSYSTEM AND OPPORTUNITIES FOR YOUTHS IN ARUNACHAL PRADESH	18
अभाविप केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक देहरादून में सम्पन्न	20
THE POIGNANCE OF MANIPUR STATE AND ITS IMPACT ON NATIONAL SECURITY	21
जेएनवीयू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का पेपर लीक, अभाविप ने किया प्रदर्शन	23
THE ABVP DELEGATION SUBMITTED A MEMORANDUM TO THE VICE–CHANCELLOR OF IGNOU TO START DISTANCE COURSES IN TRIBAL AND REGIONAL LANGUAGES	24
देश में बनेंगे 157 नए नर्सिंग कॉलेज	25
THE KERALA STORY : IT IS A PRO–HUMANITY FILM	26
सीयूईटी में केन्द्रीकृत काउंसलिंग करने की मांग, अभाविप ने यूजीसी अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन	28
पश्चिम बंगाल में अभाविप कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला	29
उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर में 'सविष्कार इनसिस्ट्स' का आयोजन	30
मध्यप्रदेश में स्कूल प्रयोगशाला में मिला मानव भ्रूण, अभाविप ने मान्यता रद्द करने की मांग की	31
संघर्षों की भट्ठी में तपकर निकले नायकों पर आधारित पुस्तक 'हमारा जीवन–हमारी यादें' का लोकार्पण	32
अभाविप हिमाचल प्रदेश द्वारा 'निरवधि' सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन	34

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

तपती गर्मी पर्यावरण की चिंता भूले बैठे लोगों को भी उसकी याद दिला देती है। 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण को लेकर तरह-तरह के आयोजन किये जाते हैं। अकादमिक चर्चाएं आयोजित की जाती है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान और उसके मूल कारण, बढ़ते उत्सर्जन को कम करने को एक चुनौती के रूप में देखे जाने की बात होती है। यहीं भारत और पश्चिम का चिंतन आमने-सामने आ खड़े होते हैं।

औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप हजारों वर्षों से चली आ रही माँग आधारित उत्पादन की व्यवस्था उत्पादन के लिये माँग उत्पन्न करने की नीति पर चल पड़ी। इस नीतिगत परिवर्तन के पीछे भीमकाय उद्योगों द्वारा किये गये बेहिसाब उत्पादन को कृत्रिम माँग उत्पन्न कर बाजार में खपा देने देने की दृष्टि थी। अधिकतम मुनाफा इसका पहला और अंतिम लक्ष्य था। परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर भी उत्पादनों को प्रोत्साहन दिया गया।

आज जब नदियाँ जलहीन हो रही हैं, ग्लेशियर सिमट रहे हैं, महानगर कूड़ें के पहाड़ों को जन्म देने लगे हैं, जनसंख्या उद्योगों के निकट सिमटने से जल, जंगल और जमीन का संकट उत्पन्न हुआ है, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ लगता है मानवता को ही लील जायेंगे, ऐसे में पर्यावरण के लिये केवल दिवस मना लेना ही काफी नहीं है। यह पृथ्वी और मानवता इससे कहीं अधिक की आशा हमसे करती है।

सामाजिक जीवन में श्रम को प्रतिष्ठा मिले, रसायनों पर निर्भरता कम हो, विकास का सूचकाँक उपभोग की क्षमता के स्थान पर संतुष्टि के स्तर को बनाया जाय, ऊर्जा के नवीकरणीय रूपों को प्राथमिकता दी जाय, बचत को केवल आर्थिक संदर्भ में ही नहीं अपितु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी देखा जाय, अधिकतम आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर पूरा किया जा सके ऐसी व्यवस्था बने और इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाय।

देश-दुनियाँ में विमर्श का बिन्दु बने अनेक नकारात्मक विषय अथवा ऐसे विषय, जो मुठ्ठी भर लोगों से जुड़े हों, सकारात्मक अथवा वैश्विक महत्व के प्रश्नों को हाशिये पर धकेल देते हैं। ठीक वैसे ही, जैसे खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। भारत, जो सदैव से विश्वबंधुत्व और लोकमंगल का उदघोष करता रहा है, पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व से भी दूर नहीं जा सकता। इसके लिये हमें प्रकृति को भारतीय दृष्टि से देखना होगा, जड़ों की ओर लौटना होगा जिसकी पहल देश के छात्र-युवाओं को करनी होगी।

हार्दिक शुभकामना सहित,

संपादक

सनातन चिंतन में पर्यावरण संरक्षण

| डॉ. मयंक पाण्डेय |

विश्व इतिहास में पहली बार रशल कार्सन नामक अमरीकी महिला वैज्ञानिक ने वर्ष 1962 में छपी अपनी पुस्तक 'साइलेंट स्प्रिंग' में मानवजनित क्रिया-कलापों (जैसे रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग) और पर्यावरण क्षरण के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया। पुस्तक के प्रारम्भिक विरोध और विभिन्न चर्चाओं के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वैश्विक या स्थानीय स्तर पर होने वाले पर्यावरण के क्षरण के मूल में मानवीय क्रिया - कलाप हैं। कालांतर में पर्यावरण क्षरण के कारण एवं संभावित और व्यवहारिक समाधानों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम (स्वीडेन) में 5 जून से 16 जून' 1972 तक UN Conference on Human Environment नामक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में भारत सहित कई अन्य देशों ने हिस्सा लिया और गोष्ठी के बाद पर्यावरण एवं जैव-विविधता संरक्षण हेतु अनेक सराहनीय प्रयास किए। विश्व इतिहास में पहली बार पर्यावरण की चिंता के लिए आयोजित इस गोष्ठी की याद में प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान' है।

भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण चेतना

भारत में विश्व पर्यावरण दिवस समर्पण के साथ मनाया जाता है। सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भविष्य में भी हमारा देश विश्व के साथ कदम से कदम मिलकर इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।

परन्तु प्रश्न यह है कि क्या भारतवर्ष में भी पर्यावरण चेतना वर्ष 1972 की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के बाद आई? क्या इससे पहले हमारे देश के चिंतन प्रवाह में पर्यावरण

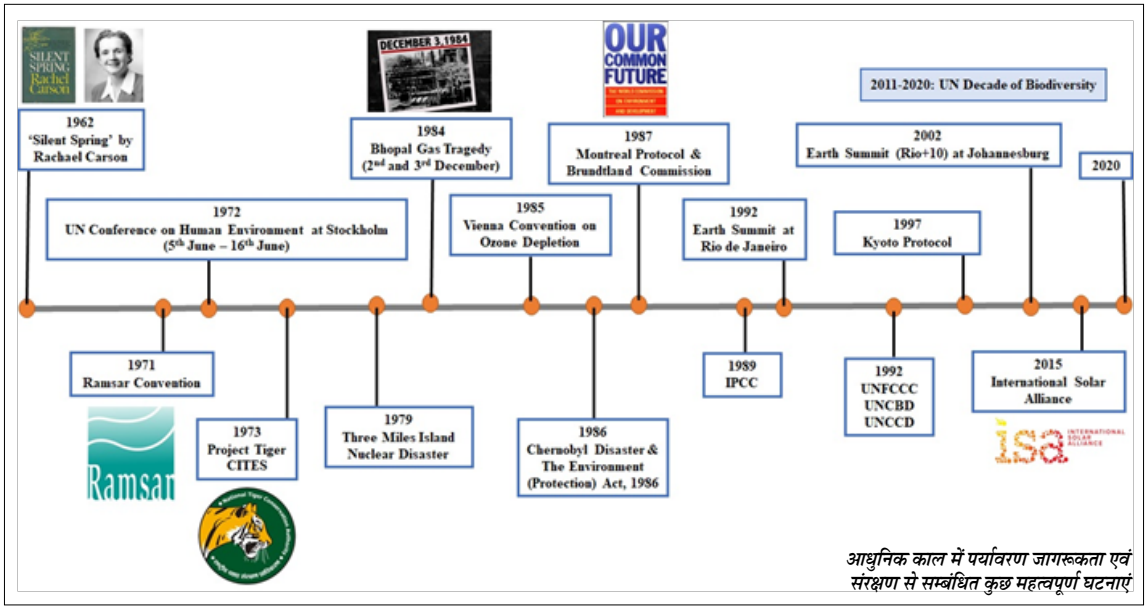

आधुनिक काल में पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं

संरक्षण की चिंता नहीं थी? क्या हमें पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाये जाने से बहुत पहले वर्ष 1950 से भारत में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने जुलाई (वर्षा ऋतु) के पहले सप्ताह में सघन वृक्षारोपण हेतु 'वन महोत्सव' की शुरुआत की थी। देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय मनीषी परंपरा ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैविक (जीव-जंतु) और अजैविक (जल, अग्नि, वायु, मृदा इत्यादि) तत्वों के आपसी-सामंजस्य एवं उपयोगिता को पहचानकर उनके महत्त्व को प्राचीन ग्रंथों में लिपिबद्ध किया और अनादि काल से देश के जनमानस में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं रीति-रिवाजों के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण के बीज बोए, जिससे वे संस्कार पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक-दूसरे में जा सके।

यत पिंडे तत ब्रह्मांडे अथवा माता भूमि पुत्रो अहम् पृथिव्या ... जैसे सूक्त इस बात के प्रमाण हैं। सनातन हिन्दू दर्शन में सभी देवी-देवताओं को किसी न किसी जीव-जंतु से सम्बद्ध दिखाया गया है। प्रकृति एवं प्राकृतिक तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नदी, पहाड़, जंगल, जीव-जंतु, ग्रह-नक्षत्र इत्यादि) को देवता-तुल्य मानकर भारतीय जनमानस प्रकृति उपासक भी बना।

16वीं शताब्दी में गुरु जम्बेश्वर द्वारा बताए गए 29 सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करने वाले बिश्नोई समाज के प्रकृति-केन्द्रित जीवनचर्या तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने जीवन का सर्वोच्च एवं अतुलनीय बलिदान करने वाली अमृता देवी विश्नोई के विषय में हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी परिचित है क्या? वर्ष 1730 में जोधपुर (राजस्थान) के सुदूर खेजरली गांव में राजा के आदेश से खेजडी के पेड़ काटने आई सैन्य टुकड़ी का निहत्थे सामना करने वाली अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी तीन बेटियों और 363 ग्रामीण नागरिकों के साथ पेड़ों से चिपक गयीं और सैनिकों को चुनौती दी कि पहले कुल्हाड़ी उनके ऊपर चलाये। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अमृता देवी, उनकी तीन बेटियों और ग्रामीणों के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें सदा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। अमृता देवी ने बेटियों और 363 ग्रामीणों सहित सैनिकों की कुल्हाड़ी से कट जाना उचित समझा, परन्तु जीवित रहते हुए अपने सामने खेजड़ी के कुछ पेड़ कटते देखना उन्हें मंजूर नहीं था। उनके अंतिम शब्द थे, 'सर सान्टे रूख रहे तो भी सस्तो जाण...' (अगर अपने प्राण गंवाकर भी पेड़ों को कटने से बचाया जा सके तो भी

यह सस्ता सौदा है)।

ऐसा माना जाता है कि 1970 और 1980 के दशक में प्रख्यात चिपको आन्दोलन की कार्यशैली (पेड़ों से चिपककर वनोन्मूलन का विरोध करना) अमृता देवी बिश्नोई की घटना से ही ली गयी थी। आज, खेजड़ी (Prosopis cineraria) राजस्थान का राजकीय वृक्ष है और भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है -अमृता देवी पुरस्कार।

पर्यावरणीय चुनौतियां एवं समाधानः भारतीय दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के समक्ष वर्ष 2015 से 2030 के बीच कुल १७ सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिन्हें पूरा करना एक गंभीर चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग-जलवायु परिवर्तन

सतत विकास लक्ष्य

और इससे होने वाले तमाम संकट अब दिखने लगे हैं। निकट भूतकाल में समूची दुनिया ने कोविड जैसी महामारी को झेला। ऐसे में आवश्यक है कि सभी देश अपने-अपने क्षमतानुसार वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कमर कस लें। भारतवर्ष अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा और नवीन वैज्ञानिक तकनीक के अद्भुत सम्मिश्रण और समन्वय से किसी भी चुनौती से निपट सकता है, ऐसा हमने अतीत में देखा है। जैव-विविधता संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता, ई-यातायात सहित आवागमन माध्यमों में क्रांतिकारी बदलाव, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन अमृत सरोवर योजना इत्यादि से सम्बंधित हाल के आंकड़े बताते हैं कि सतत विकास लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत ने नवीन और नवाचार युक्त कदम उठाए हैं। भारतीय जनमानस अपनी जड़ों से जुड़कर ही जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर का कल्याण कर सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि शताब्दियों तक जांची-परखी कार्यशैली को दैनिक जीवनचर्या में पुनः अपनाकर हम पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका निभाते हुए देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। यद्यपि, पाठक वर्ग जागरूक एवं जिम्मेदार है, तथापि, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति-केन्द्रित विकास का लक्ष्य पाने हेतु कुछ सुझाव निम्नवत हैं :

- जल संरक्षण हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाज को चाहिए कि सरकार पर पूर्ण निर्भर न होकर वर्षा जल संचयन और सरोवरों के निर्माण/उचित देख-रेख द्वारा अपने जल-स्रोत तैयार करें।
- नदियों में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, नदियों में अशोधित अपशिष्ट जल को न बहाया जाए।
- भारत की स्थानीय फसलों एवं वनस्पतियों को ही लगाया एवं प्रयोग किया जाए। भारत की स्थानीय फसलें एवं वनस्पतियाँ हमारी मृदा और जलवायु के अनुकूल होती हैं।
- गो-आधारित कृषि और पशु-पालन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो।
- उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कूड़े का वर्गीकरण एवं उसी के अनुसार निस्तारण आवश्यक है। पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर कम्पोस्टिंग को बढ़ावा दिया जाये। कूड़े को खुले वातावरण में नहीं जलाया जाए।
- प्लास्टिक और पॉलीमर उत्पादों के प्रयोग में कमी लायी जाए।
- प्लास्टिक एवं ई-कचरे का 5 R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Refurbish) पालिसी के तहत निस्तारण होना चाहिए। ■

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्य) में पर्यावरण अध्ययन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

सभी को सहभागी बनना होगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए

| राहुल गौर |

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1972 में सौ से अधिक देश संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वाहन पर पहली बार इसी दिन स्टॉकहोम में पर्यावरण की आधिकारिक चिंता करने के लिए एकत्र हुए थे। उन्हें एक मंच पर आने के लिए बाध्य किया था राचेल कार्सन नाम की एक महिला ने। 1962 में राचेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नाम से प्रकशित अपनी पुस्तक में रसायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि को होने वाले नुकसान को उल्लेखित किया था। इस पुस्तक ने दुनियाभर में विकास और पर्यावरण के संबंध में लोगों को चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया। पुस्तक के प्रभाव के रूप में क्लब ऑफ रोम ने एक और पेपर लिमिट टू ग्रोथ 1972 में प्रकाशित किया, जिसके बाद दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं विकास और इससे पर्यावरण को होने वाली क्षति पर सक्रिय बहस प्रारम्भ हुई। पिछले 50 वर्ष से विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए अलग-अलग संस्था और समूह काम कर रहे हैं, जिसका प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और विकास का पड़ा है।

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

अर्थात "समस्त परिवर्तनशील जगत में जो कुछ है, वह सब ईश्वर से आच्छादित या व्याप्त है। हमें त्याग के साथ अपना पोषण करना चाहिए और किसी के भी धन का लोभ न करें।" भारत के सम्पूर्ण पर्यावरणीय दर्शन को ईशोपनिषद के इस पहले मंत्र के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आज विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान और व्यक्ति के संतुलित एवं सच्चे विकास की बात किसी एक श्लोक में समाया है, तो वह ईशोपनिषद का यही पहला मंत्र है।

भारत में पर्यावरण के लिए आंदोलन और अभियान करने की परंपरा और उसमें समाज का सहभाग का इतिहास विश्व में सबसे पुराना है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जोधपुर के खेजड़ली में विश्नोई संप्रदाय द्वारा माता अमृता देवी के नेतृत्व में 28 अगस्त 1730 से 11 सितम्बर 1730 तक राजा के सामने किया गया आंदोलन, जिसमें 363 से ज्यादा महिला और बच्चों ने बलिदान दिया। यही आंदोलन चिपको और अपिक्को जैसे आंदोलनों का भी आधार रहा। पर्यावरण संरक्षण के अभियानों में राजस्थान के जैसलमेर में रहने वाला उस समाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिसने प्राकृतिक रूप से कम वर्षा होने के बाद स्वयं को प्रशिक्षित करते हुए जल संरक्षण की टांका पद्धति विकसित कर ली, जो आज की रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक तकनीक से कहीं ज्यादा प्रभावी है। बुंदेलखंड के वह लोग, जिनके नाम को वर्तमान समय में कोई नहीं जानता, किन्तु उनके बनाए तालाब आज भी पानी की पूर्ति करते हैं। उत्तर बिहार में हिमालय से उतरने वाली नदियों से बाढ़ आती थी और उस बाढ़ के पानी का सरंक्षण करने की तकनीक स्थानीय समाज के पास थी।

भारत की परंपरा अन्य संस्कारों की ही तरह पर्यावरण को भी संस्कार मानने की रही है। लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरण के प्रति लोग उतने संवेदनशील नहीं है, जिसका दुष्परिणाम पर्यावरण से जुडी समस्याओं के रूप में देखा जा सकता है। पर्यावरण की समस्या को समझने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के विभाजन को भी समझना होगा। बढ़ता तापमान, प्रदूषित हवा और पानी, खत्म होते जल श्रोत, भूमि उपज का कम होना, मौसम चक्र में हो रहे बदलाव जैसी जटिल समस्याएं सामने आ रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की हाल ही आई रिपोर्ट भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है ।

जोशीमठ जैसी घटनाएं जब अचानक से ध्यान खींचती हैं तो विकास के तरीकों पर कई तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सड़क बनाने का जो तरीका, किसी मैदानी भाग में दिन-रात जेसीबी चलाकर तीव्र गति से हो सकता है, क्या हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी वही तरीका प्रासंगिक है? केरल में कोच्चि के पास कचरे के ढेर में आग लगना

और प्रशासन द्वारा उसे नियंत्रित न किए जाने की स्थिति में एक सप्ताह तक स्थानीय लोगों को सांस लेने में हुई जटिल समस्या भी विकास के तरीकों पर प्रश्न पैदा करती है।

विश्विद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2023 से स्नातक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया है। निश्चित ही यह स्वागतयोग्य निर्णय है, लेकिन पर्यावरण शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी पर्यावरण चेतना है। मिशन-LiFE विश्व भर में पर्यावरण संस्कारों को ठीक करने का काम कर रहा है। एक आम नागरिक को भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वयं निर्धारित करनी होगी। पर्यावरण संस्कारों को आत्मसात करते हुए पर्यावरण के लिए कर्म करते रहना होगा। जब विकासार्थ विद्यार्थी ने वृक्षमित्र के माध्यम से वृक्षारोपण करना तय किया था, तो लक्ष्य यही था कि शिक्षा परिसरों से विद्यार्थियों में पर्यावरण संवेदना पैदा हो और वह वृक्ष के मित्र बनकर न केवल उसका रोपण करें, बल्कि उसका संरक्षण-संवर्धन भी करें।

2013 से 2021 तक नर्मदा के लिए चलाए गए सफल अभियान के केंद्र में भी जन सामान्य की सहभागिता थी। सहभागिता से जागरूकता और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी लड़ाई भी-यह पर्यावरण से जुडी समस्याओं के समाधान का कैंपस से निकला आधुनिक रास्ता है और इसका आधार भारत के पर्यावरण संस्कार ही हैं। गांव में समाज में जाना, संवाद करना, लोगों से मिलना, समस्या का अंदाजा नहीं लगाने के स्थान पर उसका अध्ययन करना, अधिक से अधिक लोगों को समाधान में सहभागी बनाना ही प्राचीन भारतीय संस्कार ही हैं। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन के अंतः संबंधों को समझना और सर्वेपी सुखिनः संतु का मूल भाव रखते हुए रोजाना प्रकृति एवं पर्यावरण के लिए कुछ न करना और इस कार्य में ने लोगों को जोड़ना ही समाधान का भारतीय मार्ग है और यही पर्यावरण दिवस की सार्थकता है। ■

(लेखक विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी) के राष्ट्रीय संयोजक हैं।)

पर्यावरण संरक्षण पर मेरठ में कार्यशाला का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा मेरठ कैंट के सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उदघाटन उद्घाटन समाज सेविका डॉ मधु वत्स, मेरठ प्रांत संगठन मंत्री महेश राठौर, विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय सह-संयोजक विपिन उनियाल तथा प्रांत संयोजक राहुल सिंह द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही अतिथियों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया।

पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका विषय पर गत 30 अप्रैल को आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय सह संयोजक विपिन उनियाल ने कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र को देश का कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषय को व्यापक चर्चाओं में सम्मिलित

किया जाए, जिससे छात्र इसके संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध रहें तथा इस कार्य के लिए आगामी भविष्य की योजनाएं तय कर सकें। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विकासार्थ विद्यार्थी मेरठ प्रांत संयोजक राहुल सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में, पर्यावरण अंतरराष्ट्रीय स्तर तक एक व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में आवश्यक है कि विद्यार्थी भी इसकी गम्भीरता को समझें और भविष्य की योजना तय करने में सार्थक भूमिका का निर्वहन करें। ■

दिल्ली में एग्रीविजन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कृषि उद्यमिता पर हुआ सारगर्भित संवाद

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम एग्रीविजन का 'स्वावलंबी कृषि-आत्मनिर्भर भारत' थीम आधारित दो दिवसीय सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के पूसा रोड स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद परिसर(आईसीएआर) में सम्पन्न हुआ। गत 5 एवं 6 मई को आयोजित सम्मेलन में देश भर के प्रमुख कृषि शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के चार सौ से अधिक छात्रों, प्राध्यापकों ने सहभागिता की तथा विभिन्न विषयों पर शोध-पत्र प्रस्तुत हुए। सम्मेलन में कृषि संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्रों में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इण्डिया के स्थापना की मांग, कृषि विश्वविद्यालयों में स्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग तथा श्रीअन्न योजना में एमएसपी को लागू करने जैसे विषय शामिल हैं।

'स्वावलंबी कृषि-आत्मनिर्भर भारत' थीम आधारित दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, आईसीएआर के उप महानिदेशक (मत्स्य विज्ञान) डॉ जयकृष्ण जेना, रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ ए के सिंह और एग्रीविजन के राष्ट्रीय संयोजक शुभम सिंह पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

श्रीअन्न के उत्पादन में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका के लिए युवा आएं आगे: कैलाश चौधरी

सम्मेलन के उदघाटन समारोह में मुख्य अतिथि केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एग्रीविजन ने कृषि क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के लिए संवाद का सार्थक मंच तैयार किया है। आज देश को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने और भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। छात्रों तथा शोधार्थियों को सरकार द्वारा चालू की गई स्टार्ट अप योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीअन्न के उत्पादन में भारत विश्व का नेतृत्व करे, ऐसी स्थिति हम सभी को मिलकर उत्पन्न करनी होगी। कृषि क्षेत्र में नई आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार सृजन की दिशा में हमें मिलकर सोचना होगा।

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान से युवाओं को दक्ष करने की आवश्यकता: आशीष चौहान

अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि भारत का कृषि क्षेत्र अत्यन्त व्यापक तथा विविध है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान द्वारा रोजगार के अधिक अवसर तलाशने होंगे तथा युवाओं को कौशल सक्षम बनाना होगा। बीते वर्षों में कृषि क्षेत्र व कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध विषयों में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ी है। कृषि विश्वविद्यालयों को यह प्रयास करने चाहिए कि कृषि छात्र को कृषि उद्यमों से जुड़ी इंटर्नशिप तथा फ़ील्ड वर्क से जुड़े कार्यों में पढ़ाई के दौरान ही संलग्न किया जाए जिससे ये छात्र भविष्य में बेहतर कर सकें।

अमृत काल में भारत जो भी करने का सोचेगा, सफल होगा : नरेन्द्र सिंह तोमर

एग्रीविजन राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान हमारा पेट भरता है, तो उसे हम संपन्न, समृद्ध या अन्नदाता किसान क्यों नहीं कह सकते? किसानों को गरीब कहने की बजाय उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, हमारे देश की रीढ़ है। हमारे जो किसान व वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे अभिनंदन के पात्र है, उन्हें सदैव प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

कृषि क्षेत्र को नवीन तकनीकी से उन्नत बनाने की आवश्यकता : शुभम सिंह पटेल

अभाविप के आयाम एग्रीविजन के राष्ट्रीय संयोजक शुभम सिंह पटेल ने कहा कि एग्रीविजन कृषि क्षेत्र की बेहतरी की दिशा में निरंतर कार्यरत है। कृषि क्षेत्र को नवीन तकनीकी से उन्नत बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह क्षेत्र लाभकारी क्षेत्र के रूप में विकसित हो सके। आज विभिन्न प्रयासों से तथा वैज्ञानिक शोधों से कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई है। ऐसे में अनुसंधान से देश के सभी किसानों को लाभ मिले, इस दिशा में हमें सभी हितधारकों को मिलकर सोचना होगा।एग्रीविजन का यह सम्मेलन बहुत सफल रहा है। आशा है कृषि विषयक कौशल विकास से सक्षम युवा देश की कृषि व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे तथा विश्व की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि क्षेत्र में प्रयास होंगे।

भारत कृषि प्रधान नहीं, कृषि उद्योग प्रधान देश है: प्रफुल्ल आकांत

'स्वावलंबी कृषि-आत्मनिर्भर भारत' थीम आधारित एग्रीविजन राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि एग्रीविजन सम्मेलन में हम एक विषय की हमेशा चर्चा करते हैं कि कृषि शिक्षा के बाद कृषि रोजगार उपलब्ध हो। भारत विश्वगुरू रहा है और इसने कभी भी किसी को दबाने का काम नहीं किया। बीते समय में आक्रमण करने वालों द्वारा भारत के हर क्षेत्र पर हमला किया गया। भारत के पास कुछ नहीं था, ऐसा नैरेटिव बनाने का एक षड्यंत्र किया गया। मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान भारत को बदलने का जो प्रयास हुए, वह जगजाहिर है। लेकिन भारत अपने स्वर्ण काल में पुनः उदित हो रहा है। काम करना भारतीय समाज जीवन की विशेष पहचान है। एक समय ऐसा था जब भारत में बने वस्त्रों को विश्व के लोट पहनते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नए-नए नियम बनाकर इसे तोड़ने का काम किया।

उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान नहीं, कृषि उद्योग प्रधान देश है। हमारी भाषा को संप्रेषण के लिए गलत बताया गया। हमारी पहचान-हमारी ताकत के बारे में दिग्भ्रमित करने का काम किया गया। स्व से दूर करने का काम हमारे साथ किया गया। इस षड्यंत्र के कारण स्वाभिमान के साथ जीने वाला समाज स्वाभिमान शून्य हो गया तथा भारत की गति रुक गई। भारत की विविधता में एकता पर आक्रमण किया गया, जिससे हमारी शक्ति क्षीण हो गई और देश जातियों में बंट गया। लेकिन भारत अब सही दिशा पर चल पड़ा है। भारत की मार्ग पर अब दुनिया भी चलने लगी है। भारत का दर्शन समाज केन्द्रित दर्शन है और उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है।Integrated Farming Agriculture की दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हजारों विचारों के साथ आगे बढ़ने पर भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्वालंबी भारत-आत्मनिर्भर भारत एग्रिविजन का विजन है। ■

SCO foreign ministers met in Delhi under a looming cloud

| K N Pandit |

The foreign ministers of the SCO met in Delhi recently; sat down, talked, ate sumptuous meals, and departed to their respective places. Some may call it sadism but it is not devoid of a grain of truth. In the lexicon of diplomacy not telling the truth is the biggest truth.

The organization started in 1996 as the Shanghai Five to connect China and Russia to their three newly independent neighbouring Central Asian States. The agenda of the first Shanghai Five spoke of building "a structure helping speed up the members' resolution of border disputes, agree on military deployments in border areas, and address security threats from terrorism. "

The SCO is primarily centred on security-related concerns, often describing the main threats it confronted coming from terrorism, separatism and extremism. Hindsight reveals that in and around 1996, Uzbekistan was faced with the terrorism of the IMU and Hizbu'tTahreer; Russian Federation was faced with separatism in Chechnya, and China was faced with the Islamic separatist movement of the Uighurs in Xinjiang.

The SCO agenda notwithstanding, these and more member states that joined the SCO in years to follow also had their national and security interests in seeking admission to the organization.

At the SCO summit, held in Tashkent, Uzbekistan, on 16–17 June 2004, the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) was established. On 21 April 2006, the SCO announced plans to fight cross-border drug crimes under the counter-terrorism rubric.

When the Shanghai Cooperation Organization had been formed and its agenda announced, in October 2007, the SCO signed an agreement with the Collective Security Treaty Organization (CSTO), in the Tajik capital of Dushanbe, to broaden cooperation on issues such as terrorism, security, crime, and drug trafficking.

China, who took the initiative of forming the SCO, and was active in framing its charter, is the foremost country among the members of the SCO, to violate its charter brazenly. China not only perpetrated atrocities on its Uighur population of 2.5 crores but went on to shield the Pakistan-based terrorists and their organizations at the Security Council and the GA.

We see that commitment to fighting terrorism in all its forms and manifestations was accepted as one of the primary concerns of the SCO. But hindsight shows that only individual and no collective response was given to these concerns.

Russia fought the Chechnya insurgency and religious extremism; Uzbekistan came down with a heavy hand on the fundamentalists and terrorists of the Islamic Movement of Uzbekistan as well as the hizbu'ttahreer – an intellectual movement for brainwashing the Muslim youth-- which had also established links with the Taliban and the Al Qaeda during the days when they held sway

over the far-off Waziristan. China suppressed the Uighur nationalist movement by a novel method of sending them to brain-washing concentration camps and at the same time promoting Han settlements in Xinjiang. It was a clear case of changing the demographic complexion of Xinjiang, once called Eastern Turkestan. We do not have any report showing a joint action under the aegis of the SCO against terrorism.

The reason for the absence of joint action is primarily the tactics of the terrorists which renders a joint or a massive action against the terrorist ineffective. The tactics generally employed is that only a small number of terrorists or suicide squads are deployed to destroy a given installation or attack a military outpost or police camp or kill unarmed people whom they consider an obstacle in the path of their mission. They throw a hand grenade at a military post and then run away to get dissolved in the crowds of people. In this way their arrest by the police or security forces on the spur of the moment becomes impossible. The security forces cannot kill innocent crowds gathered to celebrate a function and not indulge in militancy.

Strangely, the Charter of the SCO lays down that no bilateral issues will be discussed in the meetings of the organization. This is somewhat ludicrous. Tajikistan and Kyrgyzstan, the two southern Central Asian states are at loggerheads. Last year their border troops clashed in a dispute and hundreds of soldiers were killed on either side. Both are among the permanent members of the organization which did not interfere in their dispute even if there was a commitment for resolving the disputes through peaceful means. The question about this conflict has never been discussed in the SCO meetings that were held ever since the incident happened. Again, India and Pakistan, both permanent members of the organization, are at loggerheads ever since the British divided India on the basis of religion on the eve of their departure. The relations have slid down to the extent that even the fundamentals of the protocol are thrown to the winds.

There was a lot of speculation in Pakistan as well as in India whether the Pakistan foreign minister will be participating in the SCO foreign ministers meet on 4-5 May 2023 in New Delhi. The reason for speculation and media flurry was that Pakistan's foreign minister had called the Indian Prime Minister a "butcher" in his address to the UN. Such a language is unprecedented in diplomatic interaction yet Pakistan's foreign minister had no qualms of conscience.

Asked whether India would cancel the invitation to the Pakistan foreign minister to the SCO foreign minister's meet, Indian External Affairs Minister apologetically said that the invitation had been sent following the charter and practice of the SCO. Since India was hosting the meeting on the recommendation of the previous session of the SCO, she was obliged to send the invitation notwithstanding the nature of relations between the two countries.

This is a flimsy excuse and India has lost the chance of making Pakistan pay the price of indecency in conducting bilateral relations. Heaven would not have fallen if India had refused to send an invitation to Pakistan's foreign minister and simultaneously informed all other members of the organization that India cannot become a member of any international organization where a member falls to the abyss of indecency and forgets that he is supposed to speak like a statesman. India should have not only declined to send an invitation but should have also threatened to leave the SCO for the bare reason that it has failed to rein in Pakistan as the mother of global terrorism. The UN and the US both have banned at least three Pakistan-based terrorist organizations which are active in the Indian part of Kashmir. India should have also hyphened the Poonch/Rajauri terrorist attacks to Pakistan's state-sponsored terrorist agenda. We think New Delhi has missed a decisive action to pillory Pakistan. India should have boldly said that the SCO was given a death blow on the day on which China used veto power to shield Pakistani terrorists and their outfits.

It is not difficult to understand why terrorism has shifted from Kashmir Valley to Jammu

region. There is a nexus between the valley leadership and the jihadists from across the border. Finding that New Delhi was investing massively in the developmental schemes in Kashmir Valley, they implored the ISI and the jihadi leadership across the border not to disturb the developmental rush in the valley but shift the area of operation to Jammu's Poonch and Rajouri regions where jihadists can find a solid constituency of the locals to come out with logistical support to the infiltrators. The ISI has re-opened Gen Ayub Khan's Chhamb sector plan, disrupting law and order in the Jammu region with a disastrous impact on security parameters in Kashmir Valley.

It has to be reminded that Mas'udAzhar, the leader of JeM, is hiding with the Haqqani terrorist group in Afghanistan. Pakistani diehards of JeM have been receiving training and American left-behind arms and ammunition in Afghanistan with tactical instructions from ISI to shift their activities to the Jammu region where it is easier to find OGW. The G-20 meeting in Kashmir is not the only reason for exacerbating terrorism in Jammu. If Shahbaz Sharif or Imran Khan or any other Pakistani's government wants prolonged survival in power they must keep the hate-India and hate-Hindu pot boiling. The stoic silence of the valley leadership and the masses, and the intensification of terror in the jungles of Poonch and Rajouri is a low-lying tactic of the grandiose plan of Ghazavatu'l Hind. India is fighting an extremely dangerous and difficult war against two of our hostile neighbours acting in tandem. ■

रिपोर्ट

छात्रा से अभद्रता करने वाले प्राध्यापक पर कार्रवाई की मांग, अभाविप ने प्रदर्शन किया

आगरा कॉलेज में पढ़ने वाली बीएससी प्रथम वर्ष की एक छात्रा को पढ़ाने के बहाने अपने कक्ष में बुलाकर उसके साथ रसायन विभाग के सहायक प्राध्यापक द्वारा अभद्रता एवं अश्लील किये जाने के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। घटना के विरोध में परिषद ने प्रदर्शन करते हुए रोष व्यक्त किया।

परिषद ने कॉलेज के प्राचार्य को दिए एक ज्ञापन में घटना की भर्त्सना करते हुए तीन सदस्यीय वरिष्ठ प्राध्यापकों की जांच समिति बनाकर मामले की तत्काल जांच कराने और दोषी शिक्षक डॉ. राजेश वर्मा को अविलंब निलंबित करने की मांग की है, जिससे वह जांच को प्रभावित न कर सके।

अभाविप ने आरोप लगाया है कि डॉ. वर्मा पूर्व में भी इस प्रकार के कुकृत्य करते रहे हैं, लेकिन वह बचते रहे। ऐसे में इन्हें अविलंब अवकाश पर भेजा जाए तथा जांच पूरी होने तक महाविद्यालय में इनके प्रवेश को निषिद्ध किया जाए। साथ में महाविद्यालय परिसर में इनको निजी कक्ष को अविलंब वापस लिया जाए।

यह है मामला

आगरा कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ. राजेश वर्मा पर बीएससी प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने अश्लील व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि छात्रा को अतिरिक्त कक्षा देने के नाम गत 19 अप्रैल को उक्त शिक्षक ने अपने कक्ष में बुलाया और उसके साथ अभ्रदता की।

पूर्व में भी लग चुके हैं आरोप

आगरा कॉलेज के उक्त सहायक प्राध्यापक पर पूर्व में भी छात्रों के साथ अभद्रता के आरोप लग चुके हैं। परिषद का कहना है कि ऐसे शिक्षक, शिक्षा के मंदिर को दूषित कर सकारात्मक शैक्षणिक परिवेश की परिकल्पना को धूमिल कर रहे हैं। इन पर अविलंब कठोर कार्रवाई कर आगे के लिए उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए। ■

छात्र-छात्राओं की कई समस्याओं का समाधान करेगा 'नेशनल मेंटरिंग मिशन'

देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक अभियान प्रारम्भ करने जा रही हैI इस अभियान का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उन सटीक सूचनाओं की जानकारी प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपने उनके कैरियर से सम्बंधित तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी।

'नेशनल मेंटरिंग मिशन' नामक यह योजना प्रारम्भ करने की व्यापक तैयारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जा रही है। योजना का लक्ष्य यह है कि शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्रा अपने करियर के सम्बन्ध में किसी तरह के भटकाव का शिकार न होने पाए। इसी ध्यान में रखते हुए अब उन्हें शिक्षा के हर स्तर पर सलाह या परामर्श की सुविधा मिलेगी। इसका लाभ यह होगा कि छात्र-छात्राएं अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन तो कर ही सकेंगे, साथ ही उन्हें करियर बनाने के लिए भी उचित और सही जानकारियां प्राप्त हो सकेगी।

केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों की प्रगति के लिए नियमित परामर्श उपलब्ध कराने की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। छात्र-छात्राओं को शिक्षा के स्तर पर दी जाने वाली परामर्श सुविधा के मद्देनजर 'नेशनल मेंटरिंग मिशन' का एक रोडमैप तैयार किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार रोडमैप के तहत देश के चुने गए तीस स्कूलों में योजना का परीक्षण प्रारम्भ हो चुका है। परीक्षण के दौरान नेशनल मेंटरिंग मिशन योजना से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा निगाह रखी जाएगी। परीक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है।

छात्र-छात्राओं को सलाह और परामर्श देने की इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर पर भी नियम बनाने की तैयारी की गयी है, जिसके लिए मंत्रालय स्तर पर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी हैI केंद्र सरकार की योजना यह है कि नेशनल मेंटरिंग मिशन के माध्यम से छात्र-छात्राओं के साथ ही शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की भी परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी। शिक्षकों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के साथ ही छात्र-छात्राओं की प्रतिभा को पहचानने के तरीके भी सिखाए जाएंगे।

"वर्तमान में भारतीय शिक्षा क्षेत्र परिवर्तनकारी दौर में है। छात्र-छात्राओं के समक्ष चुनौतियां भी नए दौर में नई हैं, ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिध्न कदम आवश्यकता अनुसार उठाए जाने चाहिए। 'नेशनल मेंटरशिप मिशन' इस दिशा में ऐसा कदम है, जिसकी अपेक्षा शिक्षा समाज को वर्तमान में काफी समय से कर रहा है। आशा है यह मिशन छात्रों को विभिध्न स्तरों पर सहायता करने में सफल होगा।"
– याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय महामंत्री अभाविप

नेशनल मेंटरिंग मिशन के तहत सलाह या परामर्श की सुविधा देने के लिए जो नीति तैयार की गयी है, उस नीति के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षा संस्थान के स्तर पर एक परामर्श टीम का गठन किया जायेगा। परामर्श टीम में संस्थान के शिक्षकों के साथ स्थानीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर, शिक्षक, अधिकारी और उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर भी एक टीम तैयार की जाएगी। इनमें स्वैच्छिक रूप से परामर्श देने वालों के साथ ही विषय विशेषज्ञों के अतिरिक्त प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया जाएगा।

छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को परामर्श या सलाह देने का यह मॉडल मौजूदा समय में फिनलैड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों में प्रचलन में है। इन सभी देशो में हर कोई एक-दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करता आ रहा है। फिलहाल भारत में अभी ऐसा मॉडल आइआइटी संस्थानों में काम कर रहा है, जिसमें पुराने छात्र, उन नए छात्र को आगे बढ़ाने और शोध करने के लिए मदद कर रहे है, जो इस क्षेत्र में अभी काफी पिछड़े हुए है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही देश में नेशनल मेंटरिंग मिशन के तहत परामर्श का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगा। ■

जनसंख्या में वृद्धि : बोझ या वरदान...!!!

जनसंख्या के आधार पर भारत जल्द पीछे छोड़ देगा चीन को

|संजय दीक्षित|

वैश्विक देशों की सूची में भारत प्रथम स्थान पर पहुंचने की स्थिति में आ गया है और आगामी जुलाई माह के बाद भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफ़पीएफ़) ने अपनी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट-2023 में दावा किया है कि भारत की जनसंख्या 1,42.86 करोड़ हो चुकी है और जुलाई माह के बाद भारत जनसंख्या के आधार पर चीन को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट में अभी चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ बताई गयी है, जो विश्व में सर्वाधिक है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है।

यूएनएफ़पीएफ़ वह संस्था है, जो प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। यह रिपोर्ट विश्व जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकास एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती हैI यूएनएफ़पीएफ़ विशिष्ट भू-क्षेत्रों, देशों और जनसंख्या समूहों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

यूएनएफ़पीएफ़ द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट-2023 में कहा गया है कि जनसंख्या के आधार पर भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देगा और जुलाई' 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ की तुलना में, भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो जाएगी। भारत की जनसंख्या में भागीदारी को देखें तो 25 प्रतिशत 0-14 वर्ष के आयु वर्ग के, 18 प्रतिशत 10-19 आयु वर्ग के, 26 प्रतिशत 10-24 वर्ष आयु वर्ग के, 68 प्रतिशत 15-64 वर्ष आयु वर्ग के और 7 प्रतिशत 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले होंगे। रिपोर्ट यह दावा करती है कि भारत में अपने एशियाई पड़ोसी की तुलना में 29 लाख अधिक लोग होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमानित वैश्विक जनसंख्या के एक-तिहाई से अधिक होने के बावजूद, भारत और चीन दोनों ही देशों में में जनसंख्या वृद्धि धीमी रही है। वैश्विक स्तर पर भारत की कुल प्रजनन दर 2 आंकी गई है, जो विश्व औसत 2.3 से कम है। भारत के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है कि एक भारतीय पुरुष की औसत आयु 71 वर्ष और महिला की 74 वर्ष है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में होने वाली कुल अनुमानित वृद्धि में से आधी वृद्धि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया आदि आठ देशों में होगी।

वैश्विक जनसंख्या पर आई यूएनएफ़पीएफ़ की रिपोर्ट के आधार पर भारत की जनसंख्या को एक बड़े कार्यबल के रूप में देखा जा सकता है, जो देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। कारण यह है कि भारत की 68 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में है, जो कामकाजी या काम करने में सक्षम जनसंख्या में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। यह निश्चित रूप से एक जनसांख्यिकीय लाभांश की तरह देखा जा सकता है। लेकिन बड़ी जनसंख्या देश के लिए एक कठिन चुनौती भी है।

समाजशास्त्रियों की निगाह में एक लोकतांत्रिक समाज में जनसंख्या विस्फोट के कारण भोजन, सुरक्षा, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आदि क्षेत्रों में जो जटिल स्थिति बनेगी, वह संघर्ष को बढ़ावा देगी। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना ही होगा। ऐसी अनेकों चिंताओं के बीच यह जानना भी आवश्यक है कि जनसंख्या में पैदा होने वाले असंतुलन को ध्यान में रखकर चीन ने 1980 में एक बच्चे का कानून लागू किया था, जो 2016 तक लागू रहा। इसके बावजूद चीन अपनी जनसंख्या में कमी नहीं ला पाया, परन्तु अपने मानव संसाधन का

उपयोग करके चीन विश्व में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया।

भारत के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर है। बढ़ती जनसंख्या को अगर एक सशक्त मानव संसाधन के रूप में देखा जाए तो भारत में 68 प्रतिशत युवा और 48.5 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी यह बताती है कि अपने मानव संसाधन के सदुपयोग से भारत विकास की अभूतपूर्व एवं नयी ऊंचाईयों तक पहुंच सकता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सत्ता संभालने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत की स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और विश्व के विकसित से लेकर विकासशील देशों की निगाह भारत पर टिकी हुई है।

विश्लेषकों की निगाह में भारत एक बड़ी जनसंख्या के साथ ही एक विशाल और निरन्तर बढ़ रहे उपभोक्ता बाजार का प्रतिनिधित्व भी करता है, जो निवेश को आकर्षित करने में सक्षम तो है ही, साथ ही यह घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अगर अपनी युवा जनसंख्या का सही नियोजन कर लेता है तो भारत उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर बढ़ सकता है। कौशल विकास के साथ ही मानव शक्ति को सही और सटीक रूप से प्रशिक्षित करके बड़ी जनसंख्या का लाभ उसी तरह उठाया जा सकता है, जिस प्रकार से चीन ने उठाया।

देश की बढ़ती जनसंख्या और रोजगार का संतुलन न होने की स्थिति में पैदा होने वाली बेरोजगारी कई प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्या पैदा कर सकती है, जिससे असमानता, अपराध और सामाजिक अशांति जैसे नए और जटिल मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय होगा, जिससे निपटना भारी पड़ेगा। ऐसे में भारत को अपनी वर्तमान जनशक्ति का लाभ उठाने के साथ ही, जनसंख्या पर सकारात्मक रूप से नियंत्रण करने के उपायों पर ध्यान देना होगा अन्यथा बड़ी जनसंख्या देश के लिए भविष्य में एक बड़ा बोझ भी बन सकती हैI ■

Incidents of violence in Manipur unfortunate, must be resolved democratically : ABVP

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad expresses deep concern over recent incidents of violence in Manipur, which are alarming and unfortunate. India as a nation is fast rising and is coming on par with the developed nations of the world, and such news of violence in one of its integral parts of the North East is disturbing. The ABVP has always been a flagbearer of democratic principles and has always advocated for peace and coexistence in all regions of the country. We believe that any issue or problem can be solved democratically.

RK Rabichandra State Secretary of ABVP Manipur, stated, "Peaceful coexistence and a sense of brotherhood are the only paths towards humanity. We have always believed in the power of discourse and discussion to solve any challenge. The issue related to tribal reservation can only be solved through democratic means and processes. All citizens of the country must abide by the decisions of democratic bodies. The ABVP requests and appeals to everyone to maintain peace and harmony in the state."

Yagyvalkya Shukla, National General Secretary of ABVP, stated, "The North East India has always been a leading example of 'Unity in Diversity' and an epitome of coexistence, representing a beautiful example of coordination. The recent incidents of violence are really unfortunate. Dialogue and debate should be used to address any situation, and the state's law and order situation must be brought under control, with the authorities and ordinary citizens working together to ensure peace and harmony." ■

Savishkar India Exploring startup ecosystem and Opportunities for youths in Arunachal Pradesh

The Northeastern region of India has a rich cultural heritage and is known for its unique traditions, customs, and natural resources. The region also has immense potential for economic growth and development. The Indian government has initiated various schemes and policies to promote entrepreneurship and startup culture in the country.

In this context, DrPunit Kumar Dwivedi, (Professor & Group Director, Modern Group of Institutions, Indore) and National Mentor of SAVISHKAR, under the flagship of Y20 and Startup-20 visited several government educational institutions in Arunachal Pradesh and interacted with students and local entrepreneurs to promote startup opportunities in the region. National Convener Savishakar Me. Krantisagar More said, DrDwivedi's visit, highlights the challenges and opportunities for startups in Arunachal Pradesh, and provides recommendations for promoting entrepreneurship in the region which is the mission of Savishakar India. He also added Savishakar India has the tie-up with Y20 and Startup 20 for promoting entrepreneurship and Startups in the Indian startup ecosystem. The aforesaid three days visit coordinated by State Secretary TatlomTayeng in the state of Arunanchal.

Arunachal Pradesh is a northeastern state of India that is known for its scenic beauty, diverse culture, and abundant natural resources. The state is also known for its strategic location bordering China, Bhutan, and Myanmar. According to the NITI Aayog report on the Startup India initiative, the northeastern region of India has immense potential for entrepreneurial growth and development. However, the region faces several challenges such as inadequate infrastructure, difficult terrain,

and low levels of education and awareness about entrepreneurship.

Startup Opportunities in Arunachal Pradesh:

During his visit to Arunachal Pradesh, DrPunitDwivedi interacted with several local entrepreneurs and students and provided insights into various government schemes related to startups and entrepreneurship. He emphasized the importance of vocal for local and self-reliance in the region, as well as the potential for e-commerce and the best use of natural resources. He also promoted the startup ecosystem in the country and shared success stories of startups in various sectors such as healthcare, agriculture, and education.

Challenges for Startups in Arunachal Pradesh:

Despite the potential for startups in Arunachal Pradesh, the region faces several challenges. Some of the major challenges are as follows:

1. Inadequate Infrastructure: Due to the difficult terrain and lack of proper connectivity, startups face challenges in accessing markets, finance, and technology.
2. Low levels of Education and Awareness: There is a lack of awareness about entrepreneurship and startup culture in the region. This results in a shortage of skilled manpower and knowledge

about business processes and regulations.
3. Limited access to Finance: Startups in Arunachal Pradesh face difficulties in accessing finance due to the lack of venture capital firms and angel investors.

Recommendations for Promoting Entrepreneurship in Arunachal Pradesh:

To address the challenges faced by startups in Arunachal Pradesh, the government, institutions, and stakeholders need to take collective action. Some of the recommendations are as follows:

1. Improving Infrastructure: The government should focus on improving connectivity, creating proper infrastructure for startups, and developing incubation centers.
2. Strengthening Education and Awareness Programs: The government should promote entrepreneurship education, create awareness campaigns, and provide mentoring and training to aspiring entrepreneurs.
3. Increasing access to Finance: The government should facilitate access to finance by creating venture capital funds, angel investor networks, and providing tax incentives.

In conclusion, Arunachal Pradesh has immense potential for startups, and there is a need to promote entrepreneurship in the region. Dr. PunitDwivedi's visit and interactions with local entrepreneurs and students has provided valuable insights into the challenges and opportunities for startups in the region. The recommendations presented in this article can help promote entrepreneurship culture and create a favorable environment for startups in Arunachal Pradesh.

Dean, College of Horticulture & Forestry (Central Agricultural University, Imphal) Dr B.N. Hajarika, MohontoPanggingPao, Dr Temin Payum, Prof. AginTaboh, JoyaTasungMoyong& other Renowned academicians and startup owners interacted with DrDwivedi during his visit to North-East. ■

अग्निकांड पीड़ितों को अभाविप कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई सहायता

बेगूसराय के सिंहमा पथलाटोल में पिछले दिनों भीषण आग लगने से 200 परिवारों के घर जलकर राख हो गए और सैकड़ो परिवार बेघर हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) बेगूसराय नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए अपना जेब खर्चा जमा कर परिवारों के बीच चूड़ा, शक्कर, मोमबत्ती, बिस्कुट, सलाई एवं कपड़ा सहित अन्य सामग्री का वितरण किया।

विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक सोनू कुमार व जिला संयोजक पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाज हित, राष्ट्र हित एवं छात्र हित में कार्य करने वाला संगठन है। जब समाज और छात्र को परेशानी होती है, वहां अग्रणी भूमिका में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं। किसान समाज के सबसे कमजोर आदमी होते हैं, किसान कभी बाढ़ तो कभी वर्षा, कभी जानवर, तो कभी आग से प्रभावित होते रहते हैं। इन सभी चीजों से बचकर किसान देश में लिए समाज के लिए अनाज की उपज करते हैं। सिहमा के पथला टोल में आग की लपटों के साथ सभी का अनाज जल गया। इन सबों के सामने भविष्य रूपी चिंता साफ रूप से देखी जा सकती है।

नगर मंत्री दिव्यम कुमार एवं प्रदेश कार्यकारणी सदस्य आदित्य कुमार ने कहा कि अग्निकांड से बेघर परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिन-रात जुटे हैं। हमने सरकार से भी मांग की है कि पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाए जाएं एवं उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाए। वहीं 16 मई को राहत कार्य के दौरान उपस्थित अभाविप कार्यकर्ताओं ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और इसी भाव के साथ आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा जेब खर्च जमा कर सैकड़ों पीड़ित परिवार के बीच सामग्री उपलब्ध कराई गई। ■

अभाविप केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक देहरादून में सम्पन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की दो दिवसीय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक का आयोजन 25-26 अप्रैल 2023 को देहरादून में किया गया था। दून विश्वविद्यालय में दिवसीय बैठक में देश के सभी राज्यों से उपस्थित अभाविप कार्यकर्ताओं और प्राध्यापकों ने शिक्षा,समाज से जुड़े विषयों पर मंथन किया। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने देश की शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार सुधार, युवाओं को नवाचारों से जोड़ने, सभी के लिए शिक्षा की सुलभता तथा पर्यावरणीय विषयों के प्रति जागरूकता आदि विषयों पर अपने मत रखे।

बैठक का शुभारंभ अभाविप राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अभाविप राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजशरण शाही ने कहा कि देश का शिक्षा क्षेत्र संभावनाओं के यथार्थ में परिवर्तित होने के समय में है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इक्कीसवीं सदी में भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा दिखाई है। आज यह आवश्यकता है कि देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इस नीति का शीघ्रता से शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया जाए। एनसीआरएफ व एनसीएफ आदि से भी देश के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक व सकारात्मक परिवर्तन होने की आशा है। इस बदलाव की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को सहभागी होने की आवश्यकता है, जिससे देश की युवा शक्ति समर्थ नागरिक के रूप में विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। भारतीय युवा संभावनाओं को यथार्थ धरातल पर उतारने में सामर्थ्यवान है। आज की युवा शक्ति को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने में समाज व सरकार सहित देश के जिम्मेदार नागरिकों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

अभाविप की केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक में युवाओं के नेतृत्व में विभिन्न सकारात्मक गतिविधियां संचालित करने की योजना पर विचार हुआ, जिसको मूर्त रूप देने के लिए अभाविप की सभी इकाइयां तथा कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। वर्तमान में अभाविप की कुल सदस्यता 45,59,410 है तथा देश में अभाविप की 3963 इकाईयां और 8658 महाविद्यालयीन इकाईयां हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पुनीत कार्य में सतत प्रयासरत ध्येय यात्रियों की यह संख्या निरंतर विस्तारित हो रही है। अभाविप ने बीते वर्ष 589 जिलों के 5656 स्थानों पर छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें 07,01,840 युवाओं की सहभागिता रही। इन सम्मेलनों में शैक्षिक व सम-सामयिक महत्वपूर्ण विषयों के साथ स्थानीय मुद्दों पर युवाओं ने संवाद किया तथा देश के अच्छे नागरिक के रूप में अपने योगदान व भूमिका निर्वहन का संकल्प लिया। अभाविप ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन के लिए शीघ्रता से प्रयास किए जाने की मांग की है। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' मई 2023 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

The Poignance of Manipur State and its Impact on National Security

Velentina Brahma

In the wake of 4th May, the entire nation heard about the series of unfortunate events that occurred in Manipur. The recent attacks affected the areas of Churachandpur, Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Tengnoupal, and Kangpokpi and 40000 people were displaced and 40 deaths were reported.

3rd May: During the peace rally called upon on 3rd May by the All Tribal Students Union of Manipur (ATSUM), a group of Kuki protestors vandalized properties at different sites. At around 3:00 p.m., some protestors possessing sophisticated guns. Protestors attacked innocent Meeteis and destroyed their villages at Torbung, Bangla, Kangvai, and Phougakchao Ikhai and churachandpur The protestors destroyed many temples. Thay attacked Ingourok Mahadeva at Leimakhong (Kangpokpi district), Mahadeva temple at Koubru Leikha (Senapati district), temples of goddesses Kondong Lairembi and Ireima at Moreh (Tengnoupal district), etc. They vandalized 2000 traditional homes during the rally. When they destroyed Meetei traditional homes, it was akin to destroying temples as abodes of the supreme deity Salailen Sidaba (at the foundation pillar of the house), Laininghou Sannathong Apanba (at the extreme Southwest corner of the innermost room), Ima Leimarel Sidabi, Ibendhou Imoinu, etc. were destroyed. Around 4:30 pm, violence spread to the Tengnoupal district with the burning of Meetei houses by Kukis at Moreh town, bordering Myanmar. Around 5:00 pm, Kukis in Churachandpur vandalized and burnt Forest Beat Offices at Muallam and Singhat Mission Veng. Around 5:30 pm, they looted hundreds of arms and thousands of ammunition from Singhat Police Station and the Meetei-owned Churachandpur Gun House. They vandalized and burnt Meetei village Khumjamba. From around this time onwards, there were Kuki attacks on Meetei villages in Motbung in the Kangpokpi district. The agitated Meitei attacked Kuki churches in retaliation. There are some looming facts and incidences before the rally that points towards an organized planning of the violence months before. Three churches were torn down by the Manipur Government on account of illegal encroachment of government land. The Kuki Independent Army looted a large cache of arms and ammunition from Horeb SoO (Suspension of Organisation) camps in the month of April, days before the Manipur Violence. Before that, in the month of March, the Manipur government abrogated the Suspension of Organization agreement with the Kuki National Army and the Zomi Revolutionary Army(ZRA). On 28th April, a Kuki mob vandalised the inauguration of a gym at Churachandpur where Chief Minister Biren Singh was supposed to arrive as the Chief Guest of the Program.

Manipur High Court Order: ATSUM has organized this well-planned march against a high court order stating a recommendation for ST status for Meiteis, the real reasons are beyond it. First of all, the said high court order that become the crux of this protest only asked the state government to respond to a 10-year-old letter from the Ministry of Tribal Affairs asking whether or not Meiteis are a tribe on the basis of the socio-economic and ethnographic situation. Thus, the question arises why the manipulation of the public perception occurred and how under the garb of this protest certain separatist groups managed to create havoc and divide.

Geo-politics: The Meitei community lives on the plains of Manipur which constitute 10% of Manipur territory (including 2% wetland). The Kuki tribe which includes Hmar, Gangte, Paite, Chin, and Lai, along with the Naga tribes, a total of

34 STs live on the Hills of Manipur comprising the rest 90% of the land. These communities with ST statuses also reside in Mizoram state, the Jampui Hills of Tripura, internationally in some parts of Bangladesh, and unadministered areas of chin hills in Myanmar. This demography is important to understand the current scenario of Manipur.

Infiltration: The pertinent issue influencing the demography of Manipur is the unrestrained Kuki infiltration in different phases from Myanmar that have continued after independence due to either political instability or economic compulsion in Myanmar in the late 1948s, the 1960s, 1980s, and the last few years. Foreign infiltrators, by hook or crook, became Indian citizens in Manipur, became Scheduled Tribes, took advantage of the Constitution's Article 371(C) and Manipur Land Revenue and Land Reforms Act 1960, and entitled to all privileges enjoyed by indigenous tribes enlisted in the Scheduled Tribes List of Manipur.

Kukiland: The Foreign infiltrators have a rendition of Kuki Unity which is made up of Kuki, Chin, and Zou communities who aspire to create a Zalen'gam or a separate Kuki homeland or Zogam (Zomi homeland where Kuki homeland would be a part). This aspiration has been a long dream of these communities and time and again they come up with strategies and activities to move a little closer towards this dream. Recently on 12th May 2023,10 Kuki MLAs released a press statement demanding the separation of the Kuki homeland from Manipur. However, the women of Ima Market protested against the violence that occurred in Manipur and the President of Ima Market condemned these 10 MLAs for their demand saying that they should be ashamed for hurting the national integrity of Manipur.

Narcoterrorism: The irrational demand of Kukiland is funded by Narcoterrorism in Manipur. Manipur is situated in the sphere of the illicit drug trafficking network of the golden triangle. The porous borders of Manipur with Myanmar facilitate a huge influx of drugs into Manipur and for this reason, the insurgent group finds the Narcoterrorist link lucrative for funding their organization. A huge population of the Kuki community is engaged in poppy cultivation and the community believes that the poor living conditions of its people and depravity leads them to engage in illegal poppy cultivation. However, the money raised through poppy cultivation and drug trafficking is used by militant groups for their buying of weapons and land.

Initiatives by the Manipur Government: Many recent initiatives by the Manipur Government to check cross-border infiltration, population survey, war on drugs, destruction of poppy, afforestation measures, and eviction of encroachers in Protected and Reserved forests, threatens the nexus of separatist groups. Recently, when the government of Manipur initiated a campaign of 'war against drugs' an 8-hour shutdown was called by the Indigenous Tribal Leaders Forum (ITLF) against the government's move against illegal poppy cultivation. The KNA and ZRA challenged the genuine demand from indigenous communities to arrest illegal infiltration and to regulate unrestraint migration.

The Role of the Church in the entire episode of violence could not be denied. The Kuki's Tribal Churches Leaders' Forum (TCLF), Manipur openly supported the rally on the 1st of May, two days before the rally. The church endorsing political activities and openly encroaching on public land for religious practices sets an anti-state precedent for its followers undermining the authority of the law. TCLF released political statements that deem Meiteis' demand for ST as unfair and unacceptable despite the fact that the role of the Church should be restricted to religious matters only. The church should stop interfering in the political matters of the state.

The fire of the Meitei-Kuki clash has not yet subsided and the internal conflicts among communities only broaden the security threats of our country. Hence, measures of coexistence need to be taken. Both communities need to develop an understanding of National Integration and realize that we all live in one country i.e. India. ■

(The writer is Assistant Professor in Zakir Husain Delhi College, University of Delhi)

जेएनवीयू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का पेपर लीक, अभाविप ने किया प्रदर्शन

राजस्थान में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला अभी थमा ही नहीं है कि जोधपुर की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) के राजनीति विज्ञान के पेपर लीक का मामला सामने आया । गत 22 अप्रैल को जेएनवीयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभाविप ने बताया कि गत 21 अप्रैल को राजनीतिक विज्ञान के तृतीय वर्ष की परीक्षा होनी थी, परीक्षा का पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अभाविप विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष के अनुसार विश्वविद्यालय में पेपर बार-बार एक ही जगह से लीक रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे महाविद्यालय पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा । कार्रवाई नहीं होने की वजह से छात्रों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है।

परिषद की ओर से पेपर लीक मामले में दोषी महाविद्यालय एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जेएनवीयू के कुलपति को ज्ञापन दिया गया। अभाविप ने पांच सूत्री मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने के साथ पेपर लीक मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। अभाविप ने मांग की है कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार छात्र को पेपर देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अभाविप ने पेपर लीक मामले को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन में निलंबित छात्र नेता राजवीर सिंह का निलंबन वापस लेने की और राजकार्य में बाधा का मुकदमा भी वापस लेने की मांग की। इसके अलावा जिन परीक्षा केंद्र पर नकल के मामले सामने आए हैं, उन केंद्र को रद्द करने और नकल में शामिल महाविद्यालय का निलंबन तुरंत करने की मांग भी की। ■

श्रद्धांजलि

संत कनक बिहारी दास का निधन, अभाविप ने जताया शोक

यज्ञ सम्राट के नाम से प्रसिद्ध संत कनक बिहारी महाराज का गत 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर-सागर हाईवे पर बरमान के पास सड़क हादसे में निधन हो गया। बताया जाता है कि वह बरमान से छिंदवाड़ा स्थित अपने आश्रम लौट रहे थे। सड़क हादसे में उनके साथ शिष्य विश्राम रघुवंशी की मौत भी हो गई है। संत कनक बिहारी महाराज के निधन की खबर सुनते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई।

अभाविप ने उनके निधन पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक सड़क हादसे में यज्ञ सम्राट संतश्री कनक बिहारी दास जी के देवलोकगमन पर परिषद शोक संवेदना व्यक्त करती है। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में कनक बिहारी दास जी के सेवा कार्यों तथा सत्कार्य प्रेरणा ने अनेक लोगों को सकारात्मक दिशा दी।

संतश्री कनक बिहारी दास जी बाल्यकाल में ही गृह त्याग कर संन्यास परंपरा द्वारा समाजसेवा का महान लक्ष्य लिए विश्व कल्याण के पुनीत कार्य में संलग्न हो गए थे। मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले के नोनीबर्रा मे पेंच नदी के किनारे उनका आश्रम अनेक सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र रहा।

महंत कनक बिहारी दास जी महाराज मूलतः विदिशा के रहने वाले हैं और वह लंबे समय से लोनीकला श्रीराम जानकी मंदिर में ही रह रहे थे। वह लगातार विदिशा, गुना और अयोध्या में विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल होते थे। उनके हजारों शिष्य हैं और अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये चंदा दिया था। बताया जाता है कि वह फरवरी 2024 में अयोध्या में 9009 कुंडीय श्रीराम यज्ञ आयोजित करने वाले थे। अभाविप ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अनुयायियों को इस अपार दुःख को सहन करने का साहस मिले। उनके विचार, सभी को देश एवं समाज सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। ■

The ABVP delegation submitted a memorandum to the Vice-Chancellor of IGNOU to start distance courses in tribal and regional languages

A delegation led by National General Secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Yagyavalkya Shukla submitted a memorandum to IGNOU Vice-Chancellor Prof. Nageswara Rao in Delhi on 30 April, demanding that IGNOU starts offering distance courses in Indian and regional-tribal languages. ABVP has demanded that along with Indian languages, courses in tribal and regional languages should also be started for distance education and quality course material should be prepared for the same so that education can be made accessible easily for students speaking regional Indian and tribal languages.

At the moment, remarkable efforts are being made to develop course materials and books in several Indian languages for medical, pharmacy, and engineering courses. As a large number of students in India pursue distance education, ABVP determined after extensive discussions with students that the introduction of distance learning in regional and tribal languages will result in an increase in enrollment into higher education as working youth from tribal and rural areas will no longer face linguistic barriers in learning.

Yagyavalkya Shukla, National General Secretary of ABVP, stated, "Languages are not only a medium of communication, but also a carrier of culture. Today, with the implementation of the National Education Policy, changes are taking place on a large scale with the introduction of courses in Indian languages. If distance education courses in tribal and regional languages are launched, an enormous proportion of the nation's young population will be able to acquire good quality education. AkhilBharatiyaVidyarthiParishad expects that all educational institutions that provide distance education, including the Indira Gandhi National Open University, will take constructive measures in this regard." ■

देश में बनेंगे 157 नए नर्सिंग कॉलेज

केंद्र सरकार देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रही है। इसके लिए 1570 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सभी नर्सिंग कॉलेज को 24 माह में तैयार कर लिया जायेगा। जिस राज्य में जितने मेडिकल कॉलेज होंगे, वहां उतने ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार देश में जहां-जहां मेडिकल कॉलेज हैं, वहां 10 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। देश में एमबीबीएस की 1 लाख 6 हजार की है और बीएससी नर्सिंग की 1 लाख 18 हजार सीट हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने के निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया है। परिषद का मानना है कि वर्तमान में चिकित्सा आवश्यकताओं के अनुरूप देश के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र को उन्नत करने की दिशा में शीघ्रता से प्रयास करने की आवश्यकता है। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के अनुसार देश के विभिन्न जिलों में अधिक नर्सिंग सीटों की उपलब्धता होने से विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। देश के चिकित्सा ढांचे में सुधार की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता पूर्ण करने की दिशा में यह एक अच्छा कदम है।

अभाविप के आयाम मेडिविजन के राष्ट्रीय संयोजक अभिनंदन बोकरिया ने भी केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि देश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने चाहिए तथा मेडिकल शिक्षा की फीस आम भारतीयों की आर्थिक सुविधानुसार होनी चाहिए। साथ ही पहले से ही संचालित नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों में विश्वस्तरीय शोध तथा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य देश में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार अगले पांच वर्षों में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र वर्तमान 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के तहत सभी चिकित्सा उपकरण से जुड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाए जाएंगे और एक व्यापक प्रणाली के तहत चिकित्सा उपकरण बनाये जाएंगे, जिससे भारत विश्व में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके। वर्तमान में 60 से 70 प्रतिशत चिकित्सा उपकरण का आयात होता है और केंद्र सरकार का उद्देश्य इसे कम करना है। अगले 25 सालों में देश को चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़े करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

अभी हैं कितने कॉलेज

वर्तमान में देश के अंदर 5,324 नर्सिंग कॉलेज हैं। इस सूची में आगामी दो वर्ष में 157 नये कॉलेजों का नाम जुड़ जाएगा और फिर यह संख्या 5481 हो जाएगी। इस काम के लिए 1570 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली है। हर कॉलेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

इन राज्यों में बनेंगे सबसे ज्यादा कॉलेज

कुल 157 नर्सिंग कॉलेजों में से सबसे ज्यादा यानी 27 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा। इसी तरह राजस्थान में 23 कॉलेज और मध्य प्रदेश में 14 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। ■

The Kerala Story
It is a pro-humanity film

G Sreedathan

The success of a film is judged not merely on the basis of its technical brilliance or box office collection it rakes in but by the impact it generates in society. From that standpoint, the two films that have become a sort of trendsetter are The Kashmir Files and The Kerala Story. The two films have shaken the core of the society. The directors and producers of both these films have dared to go beyond their comfort zones, battling prejudices to unravel some issues that the Goliaths of the Indian film industry chose to ignore or conspired to suppress. They deserve full praise for their efforts and I am sure the future generations will remember them with gratitude.

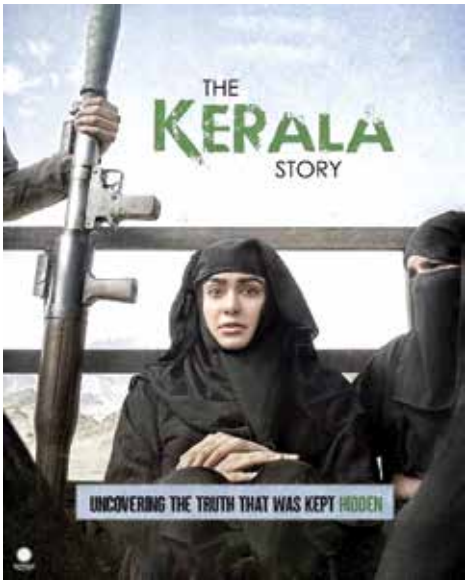

In a recent TV panel discussion on The Kerala Story, the interviewer asked me about the controversy over the 'number of girls' who were trapped in fraudulent love affairs by Islamists and trafficked to Syria and Afghanistan to fight Jihad. Although I agree with the supporters of the film that it is not the number but the issue that should be the point of discussion, I believe the number is also important. But the question is from where will we get the exact numbers? How can we get the exact numbers when there exist a hostile environment and an ecosystem which day in and day out is trying to suppress all facts about love jihad and other terror-related activities. The entire administrative system in Kerala, the police and the polity are aiding and supporting the nefarious activities of the Islamists who openly push anti-India and anti-Hindu activities. Vote-bank politics has turned the situation worse in Kerala. In the milieu, it is difficult to get the exact numbers.

Some time ago, a Christian group conducted a study in Ernakulam district. They had identified about 2500 cases where Christian girls were trapped by Islamists in the district. In most of the cases, the parents of the victims have not approached the police to file missing complaint. Fearing social stigma, several of them chose to remain silent, kept the secret close to their heart.

As the media advisor attached to Vice-Chairman of National Commission for Minorities, Shri George Kurian, I have come across several cases of 'love jihad' in Kerala and elsewhere. I have seen the plight of parents of teenage girls who were tricked into love affairs by boys who they met online. I vividly remember the case of a Delhi Christian girl whose parents approached the minority commission after she fled to a West Asian country to lead a life with a semi-literate

person whom she had met online. Immediately after she landed in the Gulf country, she was converted to Islam. The parents feared that the boy was taking her to Syria to fight jihad. By the intervention of the NCM, the girl was traced and brought to the Indian Embassy. However, she could not be brought back to India as she had turned 18 years.

The Kerala Story directed by Sudipto Sen is a realistic portrayal of the organized love trap jihad phenomenon carried out by Islamists sympathetic to Islamic State in Kerala. Victims of this activity is alive and languishing in prisons abroad. Some of them are already died. Thousands of non-Muslim women were forcibly converted weaponizing rape. According to the activists of the ArshaVidyaSamajam working among the victims of love jihad trap, they have brought more than 7,000 women back to the Sanatan fold.

It is wrong to say that the film is against a community. As DrArif Hussain Theruvath, it is the members of Muslim community who have to see the film first to know the problems within the community. In the film also, it is shown that Muslims have also become victims of Islamic radicalization. The son and daughter-in-law of a prominent Muslim League leader died in Syria fighting for Islamic State. Several doctors and engineers belonging to Muslim community have left the country to wage jihad against infidels. The film shows the perils of radicalization on humanity. As DrArif said Muslims should identify what is in the Book that encourages someone to become a human bomb. This message comes out clearly in the film. Therefore, the film is a pro-humanity film. ■

रिपोर्ट

विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) भोपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शैक्षणिक अनियमतता को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरूद्ध 13 मई को विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अभाविप ने कहा है कि भोपाल स्थित आरजीपीवी विश्वविद्यालय में कुछ माह से आर्थिक अनिमियत्ता एवं शैक्षणिक गतिविधियों के कई आरोप स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। इन आरोपों की पुष्टि कई सक्षम अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। ज्ञापन में डेस्क टॉप की खरीद में धांधली, प्राध्यापकों की पीएचडी में अनियमितता, भोजन व्यवस्था ,फर्नीचर खरीद एवं स्मार्ट क्लासरूम बनाने जैसे मुद्दों को उठाया गया है।

परिषद ने कहा कि हाल ही में घोषित हुए बीटेक, बीफार्मा, पॉलीटेक्निक के परीक्षा परिणामों में 50 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों का अनुतीर्ण होना विश्वविद्यालय की गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। परिषद मांग करती है कि विश्विद्यालय प्रशासन पर लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही सभी अनुतीर्ण विद्यार्थियों के निःशुल्क पुनः मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अभाविप के प्रदेश मंत्री आयुष पाराशर के अनुसार आरजीपीवी प्रदेश का एकमात्र तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय है। यहां छात्र कई तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हैं कि छात्रों की जो समस्याएं संज्ञान में आई हैं, उसके निराकरण के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। अगर कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती है तो अभाविप उग्र आंदोलन करेगी। ■

सीयूईटी में केन्द्रीकृत काउंसलिंग की मांग अभाविप ने यूजीसी अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार से मुलाकात करके संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) के अंतर्गत हो रही प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सीयूईटी परीक्षा के लिए और फिर विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान अलग से पंजीयन शुल्क लिए जाने के कारण छात्रों पर बढ़ रहे आर्थिक दबाव का मुद्दा उठाया। परिषद ने प्रवेश प्रक्रिया को सरल करते हुए केवल एक बार शुल्क लेने की मांग की है। साथ ही अभाविप ने आईआईटी व एनआईटी की तरह सीयूईटी के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग करने के लिए भी कहा है।

परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं सरकारी एवं विश्वसनीय केंद्रों पर ही आयोजित कराई जाएं तथा देश में सीयूईटी परीक्षा केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया जाए, जिससे छात्रों को अंतिम समय में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सीयूईटी में बड़ी संख्या में छात्र भाग ले रहे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रवेश प्रक्रिया को सरल करते हुए काउंसलिंग व्यवस्था को अधिक आसान बनाया जाए। छात्रों की आर्थिक सुविधानुसार पूरी प्रवेश प्रक्रिया में शुल्क केवल एक बार लिया जाए। साथ ही परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। परिषद का मानना है कि कॉमन काउंसलिंग प्रक्रिया होने से छात्रों को आसानी होगी।

गत अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए गए प्रतिनिधिमंडल में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री हुश्यार मीणा, साक्षी सिंह, राकेश दास, बिराज विश्वास, वीरेंद्र सोलंकी, मुस्तफा अली, अंकिता पवार, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशुतोष सिंह तथा अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री शामिल थे। आयोग के अध्यक्ष प्रो कुमार ने सीयूईटी कॉमन काउंसलिंग के विषय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ■

पश्चिम बंगाल में अभाविप कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं के साथ सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में मारपीट की गई, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। अभाविप ने राज्य की ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

घटना की जानकारी देते हुए अभाविप कार्यकर्ता अतानु दास ने बताया कि गत 11 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज में तृतीय वर्ष की परीक्षा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के करीब 40 से 50 गुंडे महाविद्यालय में घुसे और सभी शिक्षकों की उपस्थिति में लात-घूसे, लोहे की छड़ों एवं धारदार हथियारों से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पिटाई की। परिषद कार्यकर्ताओं की गलती इतनी थी कि वह विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन देने गए थे। घायल अभाविप कार्यकर्ता अनिकेत डे ने आरोप लगाया कि गत 11 मई को परिषद की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे तो तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों के सामने परिषद कार्यकर्ताओं की पिटाई की। यह घटना महाविद्यालय के प्राचार्य के सामने घटित हुई है, जो परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड है।

अभाविप उत्तर बंग के प्रदेश मंत्री शुभव्रत अधिकारी के अनुसार उपरोक्त घटना के विरोध में अभाविप द्वारा 12 मई को महाविद्यालय में 12 घंटे के हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका अधिकांश छात्रों ने समर्थन किया। 12 मई को भी, जब अभाविप कार्यकर्ता छात्रों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील कर रहे थे, उस समय तृणमूल छात्र परिषद से जुड़े अराजक तत्व महाविद्यालय परिसर आए और विद्यार्थी परिषद द्वारा लगाए गए पोस्टर एवं बैनर फाड़ते हुए गाली-गलौज करने लगे। परिषद कार्यकर्ताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला दिया, लेकिन उन लोगों ने अभाविप कार्यकर्ताओं की एक न सुनी और कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। हमले में विद्यार्थी परिषद के 22 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह सभी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे थे, उस समय पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। हमले का वीडियो विभिन्न मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया भी गया, इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभाविप प्रदेश मंत्री ने कहा कि इस घटना ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि राज्य में कानून का नहीं, बल्कि सरकार द्वारा पोषित असमाजिक तत्वों का राज है। अभाविप ने घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग के पास भी शिकायत की है। अभाविप ने मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज को देखकर घटना में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए अन्यथा परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ■

सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज में तृतीय वर्ष की परीक्षा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के करीब 40 से 50 गुंडे महाविद्यालय में घुसे और शिक्षकों की उपस्थिति में लात-घूसे, लोहे की छड़ों एवं धारदार हथियारों से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला किया और उनकी पिटाई की। परिषद कार्यकर्ता विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन देने के लिए महाविद्यालय गए थे।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर में 'सविष्कार इनसिस्ट्स' का आयोजन

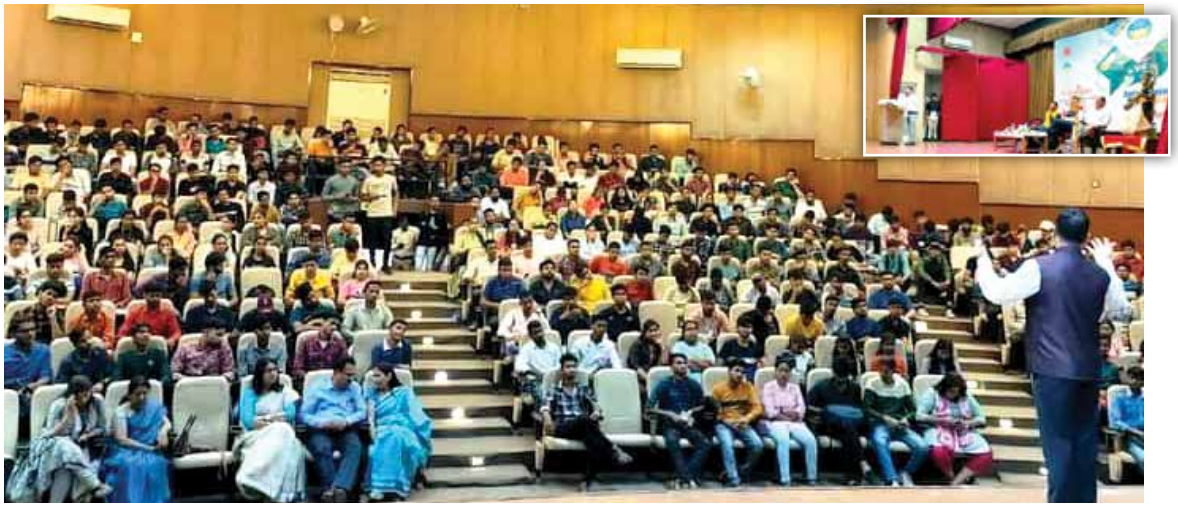

उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभाविप प्रकल्प सविष्कार द्वारा गत 5 अप्रैल 2023 को जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 'सविष्कार इंसिस्टः ए सेमिनार ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्ट- अप और इंक्यूबेशन' का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा समर्थित संस्थान मॉडर्न इनक्यूबेटर के मुख्य सलाहकार डॉ. पुनीत द्विवेदी ने कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटिलेजेंस, ए.आई.) के महत्व, उससे जुड़ी बारीकियों से विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को परिचित कराया तथा स्टार्टअप, नवाचार के माध्यम से स्वावलंबी बनने हेतु अभिनव प्रयोगों हेतु छात्रों को प्रेरित किया।

डॉ. पुनीत द्विवेदी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एवं रोबोटिक्स की उपयोगिता को प्रकाश डालते हुए स्टार्टअप की विभिन्न पक्षों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि घरेलू उद्योग भी स्टार्टअप का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। स्टार्टअप व्यवसाय शुरू करने की विधि बताते हुए उन्होंने कहा कि आप तीन बातों के से आप स्टार्टअप शुरू कर सकते है जो आपको आता है, जो आपको भाता है और जो बाजार चाहता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को एमएसएमई के बारे में बताया गया तथा विद्यार्थियों की जिज्ञासा को नई दिशा दी।

सविष्कार भारत

सविष्कार भारत, अभाविप का एक प्रकल्प है जिसके माध्यम से युवाओं में उद्यमिता और नवाचार के भाव को जगाने का काम किया जाता है। सविष्कार मुख्यतः इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, प्रबंधन से जुड़े छात्रों को स्टार्टअप से जोड़ने, उसके लिए उचित मंच प्रदान के लिए विशेषज्ञों जैसे- बैंक प्रबंधक, स्टार्टअप सीईओ, विभिन्न कंपनियों के सीईओं के साथ विभिन्न संगोष्ठी, सेमिनार इत्यादि के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाता है। सविष्कार के द्वारा इंटर्नशिप, सविष्कार इनसिस्ट्स कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। सविष्कार देश भर में युवाओं के बीच स्टार्टअप, उद्यमिता एवं नवाचार पर काम कर रही है। ■

स्कूल प्रयोगशाला में मिला मानव भ्रूण अभाविप ने मान्यता रद्द करने की मांग की

सागर (मध्यप्रदेश) जिले के बीना तहसील में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित निर्मल ज्योति कान्वेंट स्कूल की प्रयोगशाला मानव भ्रूण मिलने के विरोध में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने प्रदर्शन किया। परिषद ने स्कूल पर कार्रवाई करते हुए उसकी मान्यता रद्द करने की मांग की है। प्रयोगशाला में मानव भ्रूण होने का पता उस समय चला था, जब राज्य बाल संरक्षण आयोग की एक टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया था। प्रयोगशाला में मानव भ्रूण कैसे आया, कब आया जैसे प्रश्नों का उत्तर स्कूल प्रशासन टीम को नहीं दे सका।

राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम के छात्र रोहित कुशवाहा द्वारा निर्मल ज्योति कान्वेंट स्कूल में जबरन मतांतरण कराने की दर्ज शिकायत की जांच के लिए गत 6 अप्रैल को स्कूल पहुंची थी। टीम की जांच में मतांतरण कराने का आरोप सही पाया गया। बाद में आयोग की टीम ने स्कूल की प्रयोगशाला की जांच की, तब प्रयोगशाला में मानव भ्रूण पाया गया।

पहले बताया प्लास्टिक का है

जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन ने पहले भ्रूण को प्लास्टिक का होने की बात कही, लेकिन जब टीम सदस्यों ने प्रश्न क्या कि अगर प्लास्टिक का है, तो फिर इसे संरक्षित करके क्यों रखा गया है? अगर यह प्लास्टिक का है तो इसे बोतल में नहीं होना चाहिए। टीम के प्रश्नों का स्कूल प्रबंधन कोई उत्तर नहीं दे सका। बाद में टीम ने भ्रूण को जब्त कर मौके पर पहुंची पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया।

स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग

पहले से ही अनियमतता के घेरे में चल रहे निर्मल ज्योति स्कूल की प्रयोगशाला में मानव भ्रूण मिलने के बाद परिषद स्कूल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर एसडीएम को ज्ञापन देकर परिषद

कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। अभाविप महाकौशल प्रांत सह मंत्री सावन सिंह के अनुसार यह स्कूल कई अनियमतता के घेरे में हैं। स्कूल के छात्र रोहित कुशवाहा के पिता द्वारा स्कूल परिसर में अपने धर्म का पालन करने से रोकने एवं जबरन ईसाई मत की प्रार्थना कराए जाने सम्बंधित शिकायत की गई थी, जिसे बाल आयोग ने जांच में सही पाया।

मान्यता रद्द कर भवन किया जाए सील

अभाविप द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि स्कूल परिसर में मत विशेष की प्रार्थना कराने की शिकायत सही पाई गई है। स्कूल को मत विशेष का आराधना स्थल बना दिया गया है। पहले भी पीपलखेड़ी स्थित यूफ्रेशिया भवन, जो इसी संस्था का है, उसमें वनवासी समुदाय की बच्चियों को जबरन धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से रखा गया था और इस प्रकरण में संस्था के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। ऐसे में अभाविप कार्यकर्ताओं ने स्कूल की जांच करने और मान्यता नवीनीकरण करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए मान्यता रद्द करके भवन को सील करने की मांग प्रशासन से की है। ■

संघर्षों की भट्ठी में तपकर निकले नायकों पर आधारित पुस्तक 'हमारा जीवन-हमारी यादें' का लोकार्पण

| अजित कुमार सिंह |

नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 16 मई को रामानंद द्वारा संपादित 'हमारा जीवन-हमारी यादें' पुस्तक का विमोचन केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल द्वारा किया गया।

सामान्य परिस्थितियों में असामान्य जिजीविषा रखने वाले नायकों की कहानी

राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 136 पृष्ठों वाली पुस्तक 'हमारा जीवन-हमारी यादें' अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे चार सामान्य पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले असमान्य व्यक्तित्व की कहानियों को सामने रखती है। पुस्तक में सामाजिक समूहों के चार व्यक्तित्वों आशा लकड़ा, स्वर्गीय अनिकेत, कलीराम, धनराज के विषम परिस्थितियों तथा निरंतर संघर्ष में तपकर आगे बढ़ने की गाथा को बेहद रचनात्मक तथा सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में असामान्य जिजीविषा लिए कलीराम, आशा लकड़ा, अनिकेत तथा धनराज ने किस प्रकार अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऐसे नायकों के निर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका को भी यह पुस्तक रेखांकित करती है। पुस्तक लोकार्पण समारोह में विद्या भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख मनु शर्मा कटारिया, अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सह मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

द्वेष भावना से नहीं, देश भावना से समाज को जोड़ता है संघ : सुनील आंबेकर

पुस्तक लोकार्पण समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि हमारा जीवन हमारी यादें पुस्तक के नायक हमारे आसपास हैं। विद्यार्थी परिषद या संघ का विचार सोच को व्यापक बनाता है। वह व्यक्तियों को द्वेष से नहीं, देश प्रेम से भर देता है और अपनी ही व्यवस्था में कार्यकर्ता बनाकर नहीं रखता है, बल्कि देश सेवा और व्यक्तिगत जीवन में भी आगे बढ़ने का मौका देता है। इस यात्रा में लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि जीवन में अगर कोई संकट आता है तो, वह अपना रास्ता स्वयं निकालते हैं। यह उन परिस्थितियों के दबाव के शिकार नहीं बनते हैं और वह परिस्थितियों के दबाव में नकारात्मक न होकर, सकारात्मक रास्ता चुनते हैं। उपर्युक्त विचार को यह पुस्तक बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है।

लोगों के दिलों को जोड़ने से आता है परिवर्तन : भूपेन्द्र यादव

पुस्तक लोकार्पण समारोह में केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि हम सभी कहानियों के संसार में रहते हैं, प्रत्येक कहानी का एक उद्देश्य होता है। पुस्तक में प्रस्तुत कहानियों में केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि वातावरण का भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुतीकरण हुआ है। पुस्तक समाज के विभिन्न मर्मस्पर्शी पक्षों को समेटे हुए है, कहानी के नायकों की सफलता को 'हमारा जीवन-हमारी यादें' पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत

करती है। सामाजिक सद्भाव भाषणों से नहीं आता, सभी को हृदय में जगह देने से आता है। परिवर्तन लोगों की दिलों को जोड़ने से आती है। यह पुस्तक इसी भाव की सुंदर अभिव्यक्ति है। भगवान बुद्ध और संघ के विचार एक है।

साधारण लोगों के असाधारण कार्यों का दस्तावेज है यह पुस्तक : हर्ष चौहान

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि यह पुस्तक केवल कार्यकर्ताओं के जीवन को प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि साधारण लोग असाधारण काम कैसे करते हैं, उसका दस्तावेज भी है। ऐसी कहानियों से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, यह पुस्तक जो भी पढ़ेगा, उसके भीतर यह आत्मविश्वास जागृत करेगी कि हम भी बेहतर कर सकेंगे। अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. यशवंत राव केलकर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केलकर जी के योगदान एवं उनके विचारों से परिषद कार्यकर्ता परिचित हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सांस्थानिक स्मृतियों को बहुत ही शिद्दत के साथ सहेजा जाता है। यह पुस्तक कार्यकर्ताओं को अभाविप जैसे संगठन के बारे में जुड़ने पर उठने वाले नए प्रश्न का उत्तर देगी।

युवाओं को दिशा दिखाने का काम करेगी पुस्तक : याज्ञवल्क्य शुक्ल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि छोटे-छोटे संकटों से टूटकर बिखरने वाले युवाओं को दिशा दिखाने वाली कहानियां इस पुस्तक में हैं। यह ऐसी जीवंत गाथा है जो अभाव में प्रभाव डालने का कार्य करती है, जिसे संकलित करने का प्रयास है।

ऐसी कहानियां सामने आती रहेगी : रामानंद

हमारी जीवन-हमारी यादें पुस्तक के संपादक रामानंद ने कहा कि चार कहानियों के नायक दिखने में सहज-सरल हैं लेकिन प्रेरणास्रोत हैं। इस पुस्तक के माध्यम से यह पहला प्रयोग है। आगे भी इस प्रकार की कहानियां सामने आती रहेगी। ■

रिपोर्ट

छात्र-छात्राओं पर तेलंगाना पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई निंदनीय: अभाविप

तेलंगाना पुलिस द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) प्रदेश मंत्री सहित कई अन्य पर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस की कार्रवाई को अभाविप ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अभाविप ने कहा है कि तेलंगाना में शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रही अभाविप तेलंगाना की प्रदेश मंत्री कुमारी झांसी सहित अन्य छात्रों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार, मारपीट तथा झूठे मुकदमे दर्ज करने की घटना निंदनीय है। तेलंगाना में पुलिस छात्र-छात्राओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अभाविप तेलंगाना प्रदेश इकाई की प्रदेश मंत्री कुमारी झांसी व अन्य छात्र-छात्राओं द्वारा राज्य में अवैधानिक तरीके से चल रहे गुरुनानक विश्वविद्यालय और श्रीनिधि विश्वविद्यालय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु गत 11 मई को तेलंगाना उच्च शिक्षा परिषद कार्यालय पर शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन किया था। परिषद का आरोप है कि अवैधानिक तरीके से चल रही ऐसी संस्थाओं के कारण चार हज़ार से अधिक छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय किया हो रहा है। धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं के विरुद्ध पुलिस ने अपराधियों जैसा व्यवहार किया। उन्हें सड़क पर घसीटा गया और बाद में पुलिस स्टेशन ले जाकर मारपीट की गयी। इस पुलिसिया कार्रवाई के दौरान कुमारी झांसी की स्थिति बिगड़ गयी, जिन्हें बाद में चिकित्सक के पास जाना पड़ा।

तेलंगाना पुलिस के कार्रवाई की निंदा करते हुए परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि तेलंगाना में बेलगाम तानाशाह सरकार सत्ता में है और छात्रों-युवाओं को लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने और भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने के कारण पुलिस का उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। युवाओं पर इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई तेलंगाना सरकार के वास्तविक युवा विरोधी चरित्र को सामने लाती है। परिषद ने छात्र-छात्राओं पर पुलिस ज्यादती करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। ■

अभाविप हिमाचल प्रदेश द्वारा 'निरवधि' सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा गत 3 एवं 4 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में 'निरवधि' नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एचपीयू सभागार में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिमाचली संस्कृति देखने को मिली। इस दौरान विद्यार्थियों ने अलग-अलग क्षेत्रों की नाटियां व अन्य नृत्य पेश कर दर्शकों का मनोरंजन किया और हिमाचल की संस्कृति को भी दर्शाया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने सभागार में उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। प्रसिद्ध सुकेती नाटी ऊंची धारा तेरा डेरो ओर शिकारी मआ की प्रस्तुति आकर्षण का केन्द्र रहा।

सरस्वती वंदना से शुरू हुए इस कार्यक्रम के पहले दिन जोगिन्द्रा बैंक के निदेशक योगेश भारतीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री गुलाम मुस्तफा अली एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास सूद उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश इकाई मंत्री इंद्र नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिषद संस्कृति को संजोए रखने के लिए समय-समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। विशिष्ट अतिथि अभाविप राष्ट्रीय मंत्री गुलाम मुस्तफा अली ने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति को संजोए रखने का संदेश दिया।

वीर सावरकर पर आधारित प्रस्तुति को देख भावुक हुए दर्शक

एचपीयू में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर एक नाट्य प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुति के दौरान वीर सावरकर के संघर्षों एवं मातृभूमि के प्रति उनके त्याग को देखकर दर्शक भावुक हो उठे। सभागार तालियों से गूंज रहा था, जहां दर्शक झूम रहे थे, वहीं सभी दर्शकों की आंखे नम थी। दूसरे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध पर्वतारोही बलजीत कौर, विशिष्ट अतिथि के रूप मंस उपस्थित अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विजय प्रताप व कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेन्द्र शौरी ने निरवधि कार्यक्रम की सराहना की।

अभाविप एचपीयू इकाई अध्यक्ष करण भटनागर के अनुसार परिषद के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण सिरमौरी नाटी, कुलवी नाटी, शिमला नाटी, सुकेती नाटी, सिराजी नाटी, छौहारा नाटी, लाहौली गरफी, किन्नौरी कायंग, स्पीति नाटी, कांगड़ी जमाखड़ा, चम्बयाली नाटी, बिलासपुरी गिद्दा, भांगड़ा, मराठी नृत्य, नाटक, राजस्थानी नृत्य, हरियाणवी नृत्य, मॉडलिंग, योग प्रदर्शन गरबा (गुजराती नृत्य) आदि रहे। कार्यक्रम प्रमुख सचिन राणा ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में 300 से अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। परिषद के द्वारा समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ■

अभाविप द्वारा व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन छात्राओं ने लिया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

अभाविप ब्रज प्रांत के अलीगढ़ इकाई द्वारा मई के दूसरे सप्ताह में व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। सात दिन दिन चले विद्यार्थी परिषद के व्यक्तित्व विकास शिविर में 85 छात्राओं ने आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट व आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटीशियन, मेहंदी, सिलाई व्यक्तित्व विकास के लिए इंग्लिश स्पीकिंग, योगा, भाषण का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के समापन समारोह में सीओ बरला, विशेष उपस्थिती बाल संरक्षण आयोग जिला मजिस्ट्रेट नीता वार्ष्णेय, महानगर अध्यक्ष डॉ सौरभ सेंगर, मुख्य वक्ता डॉ तनवी शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रधानाचार्य धर्म समाज इंटर कॉलेज कौशलेंद्र यादव, कार्यक्रम सह सयोजक महक सक्सेना ने भाग लिया।

सीओ बरला सर्जना सिंह ने बताया छात्राओं को मुसीबत के समय काम आने वाली वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्प लाइन नंबर 181, चिकित्सीय सहायता के लिए 108 तथा पुलिस सहायता के लिए 112 व चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी जानकारी दी। ■

अभाविप हिमालच प्रदेश द्वारा एचपीयू, शिमला में आयोजित 'निरवधि' सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देते प्रतिभागी

सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हुई हिंसा के विरोध में धरना–प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

RNI NO.: DELBIL/2017/73636 POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI

एग्रीविजन राष्ट्रीय सम्मेलन की झलकियां